GAD SAMVEDNA
17 November, 2019

अनुसंधान से वनों की दशा सुधारेगा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

देहरादून, गद संवेदना संवाददाता। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (भा.वा.अ.शि.प.) देहरादून अनुसंधान से वनों की दशा को सुधारेगा। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (भा.वा.अ.शि.प.) देहरादून, देशभर में फैले इसके नौ अनुसंधान संस्थानों तथा पाँच केन्द्रों के माध्यम से पारिस्थितकी को वहन करने के लिए राष्ट्रीय महत्ता के वानिकी अनुसंधान मुद्दों तथा भारतीय वनों एवं रोपणियों की उत्पादकता में संवृद्धि के लिए कार्य करेगा। नई दिल्ली में प्रकाश जावडेकर, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में 15 नवम्बर 2019 को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण की प्रबंध निकाय की बैठक में डॉ. सुरेश गैरोला, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. ने विस्तृत योजना "पारिस्थितिकीय संवहनीयता तथा उत्पादकता संवृद्धि के लिए वानिकी अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण" को प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण के प्रबंध निकाय ने भा.वा.अ.शि.प. की योजना का 313.67 करोड़ रुपये को पूर्णतः अनुमोदित किया। भारत की प्रमुख वानिकी परिषद् के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक क्षण है कि इसके सूत्रपात से अब तक इस मुख्य योजना को सरकार द्वारा वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार हेतु अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय महत्व की अनुसंधान समस्याओं के सम्बोधन के लिए वानिकी अनुसंधान को अति आवश्यक वित्तपोषण की प्राप्ति होगी जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध देश के वन आरोग्यता तथा वन आधारित लोगों की आजीविका एवं कृषि पर होगा। इस योजना के माध्यम से, भा.वा.अ.शि.प. तथा इसके संस्थान 31 मुख्य अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करेंगे जिससे आरोग्यता व उत्पादकता में सुधार होगा तथा वनों एवं रोपणियों के निम्नीकरण की पुनर्प्राप्ति होगी। महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के कृन्तकों एवं किस्मों का विकास किया जाएगा तथा कृषकों एवं राज्य वन विभागों को रोपित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। वृक्ष चारा, ईंधन–काष्ठ, अकाष्ठ वन उत्पाद, वन्य फलों, मृदा नमी, जैवविविधता, संरक्षण एवं व्याधियों के महत्वपूर्ण विषय–क्षेत्रों का भी निवारण किया जाएगा। वन आनुवंशिक संसाधन (एफ.जी.आर.) संरक्षण महत्ता का एक अन्य क्षेत्र है जिस पर राष्ट्रीय स्तर संतति व भविष्य के वंशों के जीन भण्डार के संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा।"राज्य रेड्डु कार्य योजना" को तैयार करने के लिए राज्य वन विभागों का क्षमता निर्माण इस योजना का तीसरा घटक है।

कृषि नीति की तर्ज पर वन नीति अनुसंधान सरकार को विभिन्न नीतियों की संकल्पना तथा वर्तमान वन नीतियों के प्रभावों के अध्ययन में आवश्यक नीति निर्देशन प्रदान करेगा। इस पहलु को योजना के चतुर्थ घटक द्वारा विवेचना की जाएगी। वानिकी अनुसंधान में

महानिदेशक डॉ. सुरेश गैरोला

प्रौद्योगिकीयों के लिए पहुँच (आउटरीच) कार्यक्रम सबसे कमजोर कड़ी रहा है। इसका सुदृढ़ीकरण इस योजना "भा.वा.अ.शि.प. की वानिकी विस्तार योजना" के माध्यम से होगा। हितधारकों तक पहुँचना ही इस घटक की मुख्य विषय–वस्तु है। नवीन क्षेत्रों में वैज्ञानिक क्षमताओं की संवृद्धि के लिए मानव संसाधन विकास को इस योजना के माध्यम से संबोधित किया जाएगा। भा.वा.अ.शि.प. संस्थान पहले से ही देश की 13 मुख्य नदियों की जीर्णोद्धार योजना के निर्माण पर कार्य कर रहे हैं। नई दिल्ली में 15 नवम्बर 2019 को अनुमोदित नई योजना राष्ट्रीय महत्ता के मुद्दों के सम्बोधन के लिए भा.वा.अ.शि.प. की संवृद्ध क्षमता में और अधिक विस्तृत रूप से जुड़ती है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (भा.वा.अ.शि.प.) देहरादून, देशभर में फैले इसके नौ अनुसंधान संस्थानों तथा पाँच केन्द्रों के माध्यम से पारिस्थितकी को वहन करने के लिए राष्ट्रीय महत्ता के वानिकी अनुसंधान मुद्दों तथा भारतीय वनों एवं रोपणियों की उत्पादकता में संवृद्धि के लिए कार्य करेगा। नई दिल्ली में श्री प्रकाश जावडेकर, माननीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 15 नवम्बर 2019 को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण की प्रबंध निकाय की बैठक में डॉ. सुरेश गैरोला, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. ने विस्तृत योजना "पारिस्थितिकीय संवहनीयता तथा उत्पादकता संवृद्धि के लिए वानिकी अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण" को प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण के प्रबंध निकाय ने भा.वा.अ.शि.प. की योजना का 313.67 करोड़ रुपये को पूर्णतः अनुमोदित किया। भारत की प्रमुख वानिकी परिषद् के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक क्षण है कि इसके सूत्रपात से अब तक इस मुख्य योजना को सरकार द्वारा वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार हेतु अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय महत्व की अनुसंधान समस्याओं के सम्बोधन के लिए वानिकी अनुसंधान को अति आवश्यक वित्तपोषण की प्राप्ति होगी जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध देश के वन आरोग्यता तथा वन आधारित लोगों की आजीविका एवं कृषि पर होगा। इस योजना के माध्यम से, भा.वा.अ.शि.प. तथा इसके संस्थान 31 मुख्य अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करेंगे जिससे आरोग्यता व उत्पादकता में सुधार होगा तथा वनों एवं रोपणियों के निम्नीकरण की पुनर्प्राप्ति होगी। महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के कृन्तकों एवं किस्मों का विकास किया जाएगा तथा कृषकों एवं राज्य वन विभागों को रोपित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। वृक्ष चारा, ईंधन–काष्ठ, अकाष्ठ वन उत्पाद, वन्य फलों, मृदा नमी, जैवविविधता, संरक्षण एवं व्याधियों के महत्वपूर्ण विषय–क्षेत्रों का भी निवारण किया जाएगा। वन आनुवंशिक संसाधन (एफ.जी.आर.) संरक्षण महत्ता का एक अन्य क्षेत्र है जिस पर राष्ट्रीय स्तर संतति व भविष्य के वंशों के जीन भण्डार के संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा।"राज्य रेड्डु कार्य योजना" को तैयार करने के लिए राज्य वन विभागों का क्षमता निर्माण इस योजना का तीसरा घटक है। कृषि नीति की तर्ज पर वन नीति अनुसंधान सरकार को विभिन्न नीतियों की संकल्पना तथा वर्तमान वन नीतियों के प्रभावों के अध्ययन में आवश्यक नीति निर्देशन प्रदान करेगा। इस पहलु को योजना के चतुर्थ घटक द्वारा विवेचना की जाएगी। वानिकी अनुसंधान में प्रौद्योगिकीयों के लिए पहुँच (आउटरीच) कार्यक्रम सबसे कमजोर कड़ी रहा है। इसका सुदृढ़ीकरण इस योजना "भा.वा.अ.शि.प. की वानिकी विस्तार योजना" के माध्यम से होगा। हितधारकों तक पहुँचना ही इस घटक की मुख्य विषय–वस्तु है। नवीन क्षेत्रों में वैज्ञानिक क्षमताओं की संवृद्धि के लिए मानव संसाधन विकास को इस योजना के माध्यम से संबोधित किया जाएगा।भा.वा.अ.शि.प. संस्थान पहले से ही देश की 13 मुख्य नदियों की जीर्णोद्धार योजना के निर्माण पर कार्य कर रहे हैं।

THE HAWK
17 November, 2019

ICFRE Will Improve Status Of Forests Through Research Interventions

Dehradun: Dehradun based Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) along with its nine research institutes and five centres spread across the country will be working on forestry research issues of national importance for sustaining ecology and enhancing productivity of Indian forests and plantation. In the meeting held at New Delhi on 15 November 2019 of the governing body of National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (National-CAMPA) chaired by Shri Prakash Javadekar, Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change, Dr. S.C. Gairola, Director General, ICFRE presented the detailed scheme "Strengthening Forestry Research for Ecological Sustainability and Productivity Enhancement". The National CAMPA Governing body approved Rs. 313.67 crores scheme of ICFRE in toto that will be spread over five years. This is the watershed moment in the history of the premier forestry Council of India that such a major scheme has been approved by the Government for forestry research and extension since its formation in 1988. Forestry research will get the much required funds for addressing the research problems of national importance that will have direct bearing on the forest health of the country and livelihood of people dependent on forest and agriculture. Through this scheme, ICFRE and its Institutes will be working on 31 major All India Coordinated Research Projects that will improve health, productivity and restore degradation of forests and plantation. Clones and varieties of important tree species will be developed and provided to farmers and state forest departments for plantation. Important topics of tree fodder, fuelwood, NTFP, wild fruits, soil moisture, biodiversity, conservation and diseases will also be addressed.

Forest Genetic Resource (FGR) Conservation is another area of importance that will be taken up at the national level to conserve the gene pool for posterity and future generation.

Capacity building of State Forest Departments for preparing "State REDD+ Action Plan" is the third component of scheme.

Forest Policy Research on the lines of Agriculture policy will provide the much needed policy guidance to the Government in designing various policies and studying the impacts of existing forest policies. This aspect will be dealt by the 4th component of the scheme. Outreach program for extension of technologies had been the weakest link in the forestry research. This will be strengthened through this scheme by adopting the "Forestry Extension Plan of ICFRE". Reaching out to stakeholders is the centre theme of this component of ICFRE.

Human resource development to enhance the scientific capabilities of scientists in newer areas will also be addressed through the scheme.

ICFRE institutes are already working on the preparation of rejuvenation plans of 13 major rivers of country. The new scheme approved on 15th November 2019 at New Delhi further adds to its enhanced capabilities to address the issues of national importance.

THE HIMACHAL TIMES
17November, 2019

ICFRE Dehradun to improve status of forests through research interventions

DEHRADUN, NOV 16 (HTNS) Dehradun based Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) along with its nine research institutes and five centres spread across the country will be working on forestry research issues of national importance for sustaining ecology and enhancing productivity of Indian forests and plantations.

In the meeting held at New Delhi on 15 November of the governing body of National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (National-CAMPA) chaired by Prakash Javadekar, Minister of Environment, Forest and Climate Change, Dr SC Gairola, Director General, ICFRE presented the detailed scheme "Strengthening Forestry Research for Ecological Sustainability and Productivity Enhancement". The National CAMPA Governing body approved Rs 313.67crores scheme of ICFRE that will be spread over five years. This is a notable moment in the history of the premier Forestry Council of India that such a scheme has been approved by the Government for forestry research and extension since its formation in 1988.

It is being hoped that Forestry research will now get the much required funds for addressing the research problems of national importance that will have direct bearing on the forest health of the country and livelihood of people dependent on forest and agriculture. Through this scheme, ICFRE and its Institutes will be working on 31 major All India Coordinated Research Projects that will improve health, productivity and restore degradation of forests and plantation.

Clones and varieties of important tree species will be developed and provided to farmers and state forest departments for plantation. Important issues of tree fodder, fuelwood, NTFP, wild fruits, soil moisture, biodiversity, conservation and diseases will also be addressed.

Forest Genetic Resource (FGR) Conservation is another area of importance that will be taken up at the national level to conserve the gene pool for posterity and future generation.

Capacity building of State Forest Departments for preparing "State REDD+ Action Plan" is the third component of scheme.

Forest Policy Research on the lines of Agriculture policy will provide the much needed policy guidance to the Government in designing various policies and studying the impacts of existing forest policies. This aspect will be dealt by the fourth component of the scheme.

DAINIK JAGRAN
17 November, 2019

कैंपा में आइसीएफआरई को मिलेंगे 313 करोड़

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जावड़ेकर की बैठक में दी गई स्वीकृति, क्षतिपूरक वनीकरण की दिशा में करेंगे काम

जागरण संवाददाता, देहरादून: भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आइसीएफआरई) को कैंपा (कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी) से क्षतिपूरक वनीकरण के लिए 313.67 करोड़ रुपये मिलेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की बैठक में यह निधि स्वीकृत की गई।

आइसीएफआरई के महानिदेशक डॉ. एससी गैरोला ने कहा कि उनकी तरफ से बैठक में 'पारिस्थितिकीय संवहनीय व उत्पादकता संवृद्धि के लिए वानिकी अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण' विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। वन संवर्धन की दिशा में परिषद की विशेषज्ञता को देखते हुए ही यह निधि स्वीकृत की गई है। महानिदेशक ने बताया कि परिषद के अधीन वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) समेत देशभर के नौ संस्थान कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण व इसके तमाम पहलुओं पर काम किया जाएगा। साथ ही संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर की 31 परियोजनाओं पर काम कर लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। ताकि वनों की आरोग्यता बढ़ाने व वन संवर्धन में अपेक्षित परिणाम हासिल किए जा सकें।

THE PIONEER
18 November, 2019

the pioneer
DEHRADUN | MONDAY | NOVEMBER 18, 2019

ICFRE to improve status of forests through research interventions

National CAMPA governing body approves ₹313.67 crore scheme of ICFRE

PNS ■ DEHRADUN

The Dehradun-based Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE), along with its nine research institutes and five centres spread across the country, will be working on forestry research issues of national importance for sustaining ecology and enhancing productivity of Indian forests and plantations. In the meeting of the the governing body of National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (National-CAMPA), chaired by Union Minister for Environment, Forests and Climate Change, Prakash Javadekar in New Delhi recently, the ICFRE director general, SC Gairola, presented the detailed scheme for strengthening forestry research for ecological sustainability and productivity enhancement.

The National CAMPA governing body approved ₹313.67 crore scheme of ICFRE in toto that will be spread over five years.

According to officials, this is the watershed moment in the history of the premier forestry council of India with such a major scheme being approved by the Government for forestry research and extension since its formation in 1988.

Forestry research will get the much-required funds for addressing the research issues of national importance that will have direct bearing on the forest health of the country and livelihood of people dependent on forest and agriculture.

ACCORDING TO OFFICIALS, THIS IS THE WATERSHED MOMENT IN THE HISTORY OF THE PREMIER FORESTRY COUNCIL OF INDIA WITH SUCH A MAJOR SCHEME BEING APPROVED BY THE GOVERNMENT FOR FORESTRY RESEARCH AND EXTENSION SINCE ITS FORMATION IN 1988.

FORESTRY RESEARCH WILL GET THE MUCH-REQUIRED FUNDS FOR ADDRESSING THE RESEARCH ISSUES OF NATIONAL IMPORTANCE THAT WILL HAVE DIRECT BEARING ON THE FOREST HEALTH OF THE COUNTRY AND LIVELIHOOD OF PEOPLE DEPENDENT ON FOREST AND AGRICULTURE

Through this scheme, the ICFRE and its institutes will be working on 31 major All India Coordinated Research Projects that will improve health, productivity and restore degradation of forests and plantation. Clones and varieties of important tree species will be developed and provided to farmers and State forest departments for plantation.

Important topics of tree fodder, fuelwood, NTFP, wild fruits, soil moisture, biodiversity, conservation and diseases will also be addressed.

Forest Genetic Resource (FGR) Conservation is another area of importance that will be taken up at the national level to conserve the gene pool for posterity and future generation. Capacity building of State Forest Departments for preparing State REDD+ action plan is the third component of scheme.

Forest policy research on the lines of agriculture policy will provide the much-needed policy guidance to the Government in designing various policies and studying the impacts of existing forest policies.

This aspect will be dealt by the fourth component of the scheme. Outreach programme for extension of technologies had been the weakest link in the forestry research efforts. This will be strengthened through this scheme by adopting the forestry extension plan of ICFRE". Reaching out to stakeholders is the centre theme of this component of ICFRE.

Human resource development to enhance the scientific capabilities of scientists in newer areas will also be addressed through the scheme.

ICFRE institutes are already working on the preparation of rejuvenation plans of 13 major rivers of country.

The new scheme approved further adds to its enhanced capabilities to address the issues of national importance.

RASHTRIYA SAHARA
17 November, 2019

आईसीएफआरई एवं शिक्षा परिषद करेगी इस दिशा में कार्य, 313.67 करोड़ रुपये अनुमोदित

अनुसंधान से सुधरेगी देश में वनों की दशा

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) नवीन अनुसंधान द्वारा वनों की दशा सुधारेगा। परिषद के देशभर में स्थित नौ अनुसंधान संस्थान व पांच केंद्र पारिस्थितकी को वहन करने के लिए राष्ट्रीय महत्ता के वानिकी अनुसंधान मुद्दों, भारतीय वनों व रोपणियों की उत्पादकता में संवृद्धि के लिए कार्य करेंगे।

परिषद के महानिदेशक डा. सुरेश गैरोला ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण की प्रबंध निकाय की बैठक में पारिस्थितिकीय संवहनीयता तथा उत्पादकता संवृद्धि के लिए वानिकी अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण विषय पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।

वहीं राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण के प्रबंध निकाय ने आईसीएफआरई की योजना का 313.67 करोड़ रुपये को पूर्णतः अनुमोदित किया। परिषद के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक क्षण है कि जबकि

इस मुख्य योजना को भारत सरकार द्वारा वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार हेतु अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय महत्व की अनुसंधान समस्याओं के संबोधन के लिए वानिकी अनुसंधान को अति आवश्यक वित्तपोषण की प्राप्ति होगी, जिसका प्रत्यक्ष संबंध देश के वन आरोग्यता तथा वन आधारित लोगों की आजीविका व कृषि पर होगा।

महानिदेशक डा. गैरोला ने बताया कि इस योजना के माध्यम से आईसीएफआरई व सहयोगी संस्थान 31 मुख्य अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करेंगे, जिससे आरोग्यता व उत्पादकता में सुधार होगा तथा वनों एवं रोपणियों के निम्नीकरण की पुनर्प्राप्ति होगी। महत्वपूर्ण पादप प्रजातियों के किस्मों का विकास किया जाएगा तथा कृषकों व राज्य वन विभागों को रोपित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। वृक्ष चारा, ईंधन-काष्ठ, अकाष्ठ वन उत्पाद, वन्य फलों, मृदा नमी, जैवविविधता, संरक्षण व व्याधियों के महत्वपूर्ण विषयक्षेत्रों का भी निवारण किया जाएगा।

वन आनुवांशिक संसाधन संरक्षण महत्ता का एक अन्य क्षेत्र है जिस पर राष्ट्रीय स्तर संतति व भविष्य के वंशो के जीन भंडार के संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। राज्य रेड्ड प्लस कार्य योजना को तैयार करने के लिए राज्य वन विभागों का क्षमता निर्माण इस योजना का तीसरा घटक है। कृषि नीति की तर्ज पर वन नीति अनुसंधान सरकार को विभिन्न नीतियों की संकल्पना तथा वर्तमान वन नीतियों के प्रभावों के अध्ययन में आवश्यक नीति-निर्देशन प्रदान करेगा।

इस पहलु को योजना के चतुर्थ घटक द्वारा विवेचना की जाएगी। नवीन क्षेत्रों में वैज्ञानिक क्षमताओं की संवृद्धि के लिए मानव संसाधन विकास को इस योजना के माध्यम से संबोधित किया जाएगा। बताया कि परिषद पहले से ही 13 मुख्य नदियों की जीर्णोद्धार योजना के निर्माण पर कार्य कर रहा है।

SHAH TIMES

18 November, 2019

आईसीएफआरई अनुसंधान से सुधरेगी वनों की दशा: डॉ. गैरोला

कैंप में आईसीएफआरई को मिलेंगे 313 करोड़, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के साथ हुई बैठक में मिली स्वीकृति

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (आईसीएफआरई) देहरादून, देशभर में फैले इसके नौ अनुसंधान संस्थानों तथा पांच केन्द्रों के माध्यम से

■ महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के विकास के लिए किया जाएगा शोध कार्य, कृषकों को मिलेगा लाभ

पारिस्थितकी को वहन करने के लिए राष्ट्रीय महत्ता के वानिकी अनुसंधान मुद्दों तथा भारतीय वनों एवं रोपणियों की उत्पादकता में संवृद्धि के लिए कार्य करेगा।

नई दिल्ली में प्रकाश जावडेकर, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण की प्रबंध निकाय की बैठक में डॉ. सुरेश गैरोला, महानिद. शक, आईसीएफआरई ने विस्तृत योजना ''पारिस्थितिकीय संवहनीयता तथा उत्पादकता संवृद्धि के लिए वानिकी अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण'' को प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण के प्रबंध निकाय ने आईसीएफआरई की योजना का 313.67 करोड़ रुपये को पूर्णत: अनुमोदित किया। भारत की प्रमुख वानिकी परिषद् के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक क्षण है कि इसके सूत्रपात से अब तक इस मुख्य योजना को सरकार द्वारा वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार के लिए अनुमोदित किया गया है।

राष्ट्रीय महत्व की अनुसंधान समस्याओं के सम्बोधन के लिए वानिकी अनुसंधान को अति आवश्यक वित्तपोषण की प्राप्ति होगी जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध देश के वन आरोग्यता तथा वन आधारित लोगों की आजीविका एवं कृषि पर होगा। इस योजना के माध्यम से आईसीएफआरई तथा इसके संस्थान 31 मुख्य अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करेंगे जिससे आरोग्यता व उत्पादकता में सुधार होगा तथा वनों एवं रोपणियों के निम्नीकरण की पुनर्प्राप्ति होगी।

महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के कृन्तकों एवं किस्मों का विकास किया जाएगा तथा कृषकों एवं राज्य वन विभागों को रोपित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। वृक्ष चारा, ईंधन-काष्ठ, अकाष्ठ वन उत्पाद, वन्य फलों, मृदा नमी, जैवविविधता, संरक्षण एवं व्याधियों के महत्वपूर्ण विषय-क्षेत्रों का भी निवारण किया जाएगा। वन आनुवंशिक संसाधन (एफ.जी.आर.) संरक्षण महत्ता का एक अन्य क्षेत्र है जिस पर राष्ट्रीय स्तर संतति व भविष्य के वंशों के जीन भण्डार के संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। ''राज्य रेड कार्य योजना'' को तैयार करने के लिए राज्य वन विभागों का क्षमता निर्माण इस योजना का तीसरा घटक है। कृषि नीति की तर्ज पर वन नीति अनुसंधान सरकार को विभिन्न नीतियों की संकल्पना तथा वर्तमान वन नीतियों के प्रभावों के अध्ययन में आवश्यक नीति निर्देशन प्रदान करेगा।

वानिकी अनुसंधान में प्रौद्योगिकीयों के लिए पहुँच (आउटरीच) कार्यक्रम सबसे कमजोर कड़ी रहा है। इसका सुदृढ़ीकरण आईसीएफआरई की वानिकी विस्तार योजना के माध्यम से होगा। हितधारकों तक पहुंचना ही इस घटक की मुख्य विषय-वस्तु है। नवीन क्षेत्रों में वैज्ञानिक क्षमताओं की संवृद्धि के लिए मानव संसाधन विकास को इस योजना के माध्यम से संबोधित किया जाएगा।